राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर

एस. बी. सिविल रिट याचिका सं. 7777/2020

कमला कुमारी चारपोता पुत्री श्री पंचू, आयु लगभग 30 वर्ष, गाँव लालपुरा नापला, छोटी सरवन, जिला बांसवाड़ा (राजस्थान)।

----याचिकाकर्ता

बनाम

1. राजस्थान राज्य सचिव, चिकित्सा और स्वास्थ्य विभाग, सचिवालय, जयपुर (राजस्थान) के माध्यम से।
2. अतिरिक्त निदेशक (प्रशासन), चिकित्सा और स्वास्थ्य सेवा विभाग, स्वास्थ्य भवन, तिलक मार्ग, जयपुर (राजस्थान)।
3. पंजीयक, राजस्थान नर्सिंग परिषद, जयपुर (राजस्थान)।

----प्रतिवादिगण

याचिकाकर्ता (गण) के लिए	:	श्री महेंद्र गोदारा।
प्रतिवादी (गण) के लिए	:	श्री संग्राम सिंह।
		श्री श्रेयांश मेहता।

माननीय श्री न्यायाधीश अरुण मोंगा

<u>आदेश</u>

<u>04/01/2024</u>

1. याचिकाकर्ता की शिकायत दिनांकित 05.08.2020 (अनुलग्नक 7) के आदेश से उत्पन्न होती है, जिसके अनुसार प्रतिवादी ने सहायक नर्स और मिडवाइफरी (ए. एन. एम.) के पद के लिए याचिकाकर्ता की उम्मीदवारी को खारिज कर दिया है।

2. मामले के प्रासंगिक तथ्यः

2.1. याचिकाकर्ता ने अपनी स्कूली शिक्षा पूरी की और बाद में दो साल का सहायक नर्स और दाई (ए. एन. एम.) पाठ्यक्रम पूरा किया। उन्होंने राजस्थान नर्सिंग काउंसिल अधिनियम, 1964 की खंड 13 के तहत प्रतिवादी संख्या 3-पंजीयक, राजस्थान नर्सिंग काउंसिल, जयपुर के समक्ष पंजीकरण के लिए आवेदन किया। प्रतिवादी संख्या 3 ने 28.08.2014 पर एक पंजीकरण प्रमाणपत्र जारी किया, जिसमें याचिकाकर्ता को पंजीकृत 'नर्स और मिडवाइफरी' (जी एन एम) के रूप में सूचीबद्ध किया गया।

2.2. प्रतिवादी ने अधिसूचना दिनांक 18.06.2018 के माध्यम से टीएसपी-एसटी क्षेत्र में एएनएम के पद को भरने के लिए आवेदन आमंत्रित किए। जवाब में, याचिकाकर्ता ने उक्त पद के लिए भी आवेदन किया, जिसमें याचिकाकर्ता ने 'एएनएम' के बजाय 'नर्स और मिडवाइफरी' का प्रमाण पत्र अपलोड किया, जो उसे गलत तरीके से जारी किया गया था।

2.3 याचिकाकर्ता ने 15.01.2019 (अनुलग्नक 4) पर प्रमाण पत्र में सुधार के लिए नर्सिंग परिषद में आवेदन किया। दस्तावेज़ सत्यापन से पहले उन्हें 03.06.2019 (अनुलग्नक 5) पर एक नया प्रमाण पत्र जारी किया गया था। याचिकाकर्ता सफल होने के कारण, 15.06.2019 (अनुलग्नक 3) पर दस्तावेज़ सत्यापन के लिए बुलाया। दस्तावेज़ सत्यापन के दौरान, याचिकाकर्ता के पंजीकरण प्रमाण पत्र की 'सहायक नर्स और मिडवाइफरी' के रूप में वैधता के बारे में संदेह पैदा हुआ क्योंकि उसके पहले के प्रमाण पत्र में इसे 'नर्स और मिडवाइफरी' कहा गया था। हालांकि, उसके दस्तावेजों का सत्यापन किया गया और याचिकाकर्ता को सही पंजीकरण प्रमाण पत्र जमा करने का निर्देश दिया गया। उन्होंने प्रतिवादी के सामने 04.11.2019 पर वही प्रस्तुत किया।

2.4. सही प्रमाण पत्र जमा करने के बावजूद, याचिकाकर्ता की उम्मीदवारी को इस आधार पर खारिज कर दिया गया कि पंजीकरण प्रमाण पत्र ऑनलाइन आवेदन की तारीख के बाद जारी किया गया था जो 'सहायक नर्स और मिडवाइफरी' के रूप में पंजीकरण प्रमाण पत्र होने के लिए भी कट ऑफ है।

2.5. अंतिम चयन सूची कट-ऑफ अंकों के साथ 18.01.2020 पर प्रकाशित की गई थी लेकिन याचिकाकर्ता का चयन नहीं किया गया था। कम योग्यता वाले अन्य उम्मीदवारों के पक्ष में नियुक्ति आदेश जारी किए गए थे। इसलिए, तत्काल याचिका।

3. उपरोक्त पृष्ठभूमि में, मैंने संबंधित पक्षों का प्रतिनिधित्व करने वाले वकील की प्रतिद्वंद्वी दलीलें सुनी हैं।

4. विज्ञापन दिनांक 18.06.2018 (अनुलग्नक 2) के अवलोकन पर, यह स्पष्ट है कि राजस्थान नर्सिंग परिषद से पंजीकरण प्रमाण पत्र को ऑनलाइन आवेदन पत्र के साथ अपलोड करना आवश्यक था, और पात्र होने के लिए, यह आवेदन की तारीख को या उससे पहले का होना चाहिए। यह देखते हुए कि ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि 23.07.2018 थी, इस बात पर कोई विवाद नहीं है कि राजस्थान नर्सिंग काउंसिल ('आर एन सी') द्वारा जारी किया गया 28.08.2014 का प्रमाण पत्र, जो याचिकाकर्ता की पंजीकृत नर्स और मिडवाइफ ('आर एन एम') के रूप में स्थिति की पुष्टि करता है, कटऑफ तिथि से पहले आता है। इस प्रमाण पत्र की प्रामाणिकता निर्विरोध है, और इसके आधार पर, याचिकाकर्ता को चयन प्रक्रिया में भाग लेने की अनुमति दी गई थी और बाद में इसे सफल घोषित किया गया था।

5. हालांकि, बाद में उपरोक्त प्रमाण पत्र के बारे में संदेह पैदा हुआ क्योंकि इसमें स्पष्ट रूप से 'सहायक नर्स और मिडवाइफरी' ('एएनएम') नहीं कहा गया था। एक आपत्ति उठाई गई, जिसके बाद राजस्थान नर्सिंग काउंसिल से स्पष्टीकरण का अनुरोध किया गया। नतीजतन, याचिकाकर्ता को उसी विवरण के आधार पर, जिसके कारण पहले का दिनांकित 28.08.2014 प्रमाण पत्र जारी किया गया था, एक ए. एन. एम. के रूप में उसकी स्थिति की पुष्टि करने वाला एक संशोधित प्रमाण पत्र प्रदान किया गया था। महत्वपूर्ण रूप से, यह बाद में संशोधित प्रमाण पत्र उन्हीं प्रमाण पत्रों पर आधारित है जिनके कारण पहले आर. एन. एम. प्रमाण पत्र जारी किया गया था। इसलिए, याचिकाकर्ता की अर्हता, योग्यता या शैक्षिक पृष्ठभूमि के संदर्भ में कोई बदलाव नहीं किया गया था।

6. इसके बावजूद, याचिकाकर्ता की उम्मीदवारी को इस आधार पर खारिज कर दिया गया कि बाद में संशोधित प्रमाण पत्र दिनांक 03.06.2019 ऑनलाइन आवेदनों के लिए कट-ऑफ तिथि के बाद जारी किया गया था, जिससे वह अयोग्य हो गई थी।

7. यह हैरान करने वाली बात है कि, एक ओर, प्रतिवादी याचिकाकर्ता के पास ए. एन. एम. पद के लिए आवश्यक योग्यता के अधिकार का विरोध नहीं करते हैं, न ही उसी योग्यता के आधार पर उसके पेशेवर प्रशिक्षण के पूरा होने का,

जिसने उसे ए. एन. एम. के रूप में पंजीकृत होने में सक्षम बनाया। केवल इसलिए कि पहले के प्रमाण पत्र में 'सहायक' शब्द शामिल नहीं था, बल्कि 'नर्स-सह-मिडवाइफरी' कहा गया था, इसे अस्वीकार करना मनमाना लगता है। यह उल्लेखनीय है कि नर्सिंग काउंसिल के साथ पंजीकरण के लिए याचिकाकर्ता के आवेदन में विशेष रूप से ए. एन. एम. पंजीकरण की मांग की गई थी, लेकिन नर्सिंग काउंसिल की ओर से एक निरीक्षण के कारण, उसे इसके बजाय आर. एन. एम. प्रमाण पत्र जारी किया गया था। इस बात में कोई दुविधा नहीं है कि याचिकाकर्ता के पास ए. एन. एम. के रूप में सेवा करने के लिए आवश्यक शैक्षणिक योग्यता का अभाव है। इसके अलावा, नर्सिंग परिषद के भीतर पंजीकरण, चाहे जी. एन. एम. या ए. एन. एम. के रूप में, स्वाभाविक रूप से एक पंजीकृत नर्स को विशेषज्ञता प्रदान नहीं करता है, चाहे वह एक सहायक नर्स हो या एक पंजीकृत नर्स, जब तक कि शैक्षणिक योग्यताएँ विज्ञापन आवश्यकताओं के अनुरूप हो। नर्सिंग काउंसिल के साथ पंजीकरण की आवश्यकता केवल एक औपचारिकता प्रतीत होती है और इसके लिए किसी शैक्षणिक संस्था से ए. एन. एम. का पाठ्यक्रम करने के बाद किसी और परीक्षा या साक्षात्कार या किसी अतिरिक्त योग्यता की आवश्यकता नहीं होती है।

8. इस संदर्भ में, मेरे पहले के एक फैसले जिसका शीर्षक (सीमा बनाम हरियाणा राज्य और अन्य) सिविल रिट याचिका सं. 16902/2020 दिनांकित 28.01.2022 का भी संदर्भ दिया जा सकता है, जिसे मुझे पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय में एक कनिष्ठ न्यायाधीश के रूप में प्रस्तुत करने का अवसर मिला था। इसका प्रासंगिक पैरा नीचे प्रस्तुत किया गया हैः

> "8. जैसा कि कहा गया है, पद के लिए आवेदन की कट-ऑफ तिथि 22.01.2020 थी।याचिकाकर्ता ने पंजीकरण प्रमाण पत्र के लिए दिल्ली चिकित्सा परिषद में पांच दिन पहले आवेदन किया था। सामान्य तौर पर, कोई भी यह समझने में असमर्थ है कि चिकित्सा परिषद को पंजीकरण के अनुदान के लिए आवेदन पर क्यों रोक लगानी चाहिए, जबकि यह केवल एक औपचारिकता प्रतीत होती है। इस तरह के प्रमाण पत्र के जारी करने से पहले न तो उम्मीदवार की कोई योग्यता निर्धारित की जानी चाहिए और न ही पंजीकरण किसी भी प्रकार की अतिरिक्त योग्यता है जिसके लिए परिषद द्वारा उम्मीदवार की जांच की आवश्यकता होती है। वास्तव में, पंजीकरण कमोबेश अधिकार के रूप में दिया जाता है, वह भी एकतरफा, केवल पंजीकरण प्रपत्र के लिए आवेदन की सामग्री को

आवश्यक दस्तावेजों के द्वारा जोड़कर। वास्तव में, जिस प्रक्रिया और जिस तरीके से पंजीकरण दिया जाता है, उसे देखते हुए यह राय देना उचित और न्यायसंगत लगता है कि एक बार पंजीकरण दिए जाने के बाद, चिकित्सा अधिकारी के पद के लिए आवेदन करने की पात्रता निर्धारित करने के उद्देश्य से, इसे आवेदन की तारीख से ही सुनिश्चित किया जाना चाहिए और प्रमाण पत्र पर रखी गई तारीख की केवल औपचारिकता को केवल प्रमाण पत्र जारी करने की तारीख के रूप में पढ़ा जाना है, लेकिन वास्तव में, आवेदन के आवश्यक प्रारूप के तहत आवेदन करने की तारीख से प्रभावी है। किसी भी मामले में याचिकाकर्ता को पंजीकरण के अनुदान में चिकित्सा परिषद की ओर से प्रक्रियात्मक देरी के लिए पीड़ित नहीं होना चाहिए।"

9. उपरोक्त के अलावा, प्रतिवादी का आचरण काफी असंगत प्रतीत होता है। दस्तावेज़ सत्यापन प्रक्रिया के दौरान पहले के पंजीकरण प्रमाण पत्र को शुरू में सत्यापित करने के बाद, याचिकाकर्ता को अनुमति दी गई या एक संशोधित प्रमाण पत्र जमा करने के लिए कहा गया। हालाँकि, कट-ऑफ तिथि के बाद जारी किए जाने के आधार पर बाद की अस्वीकृति विरोधाभासी है और ऐसा करने के लिए दी गई पूर्व अनुमति के विपरीत है। प्रतिवादी एक ही समय में अनुमोदन और खंडन नहीं कर सकते हैं।

10. अंत में, अलग होने से पहले इस बात पर जोर देने की आवश्यकता है कि विज्ञापन के खंड 12 में स्पष्ट रूप से निर्धारित किया गया है कि उम्मीदवारों को सत्यापन के लिए निर्धारित तिथि पर व्यक्तिगत रूप से अपनी साख और प्रमाण पत्र जमा करने की आवश्यकता थी। यह ध्यान देने योग्य है कि दस्तावेज़ सत्यापन के समय, याचिकाकर्ता को पहले ही नर्सिंग परिषद द्वारा 03.06.2019 (अनुलग्नक 5) दिनांकित एक पंजीकरण प्रमाण पत्र जारी किया जा चुका था।

11. इसके अलावा, यह रेखांकित करना उचित है कि यह एक नया प्रमाण पत्र प्राप्त करने का मामला नहीं था, जैसा कि पहले ही कहा जा चुका है, बल्कि नर्सिंग परिषद द्वारा जारी याचिकाकर्ता के पहले के प्रमाण पत्र में सुधार था, जो उसकी अपनी किसी गलती के कारण नहीं था। इसके बावजूद, याचिकाकर्ता को गंभीर परिणामों का सामना करना पड़ा है और उसे नर्सिंग परिषद की लापरवाही के लिए अन्यायपूर्ण रूप से दंडित किया गया है। प्रतिवादी की ओर से इस तरह का मनमाना व्यवहार बहुत निराशाजनक है, कम से कम कहने के

लिए, और अपेक्षित मानकों से कम है और वांछित होने के लिए बहुत कुछ छोड़ देता है।

12. मेरी चर्चा के परिणाम के रूप में, रिट याचिका की अनुमति है। यह स्पष्ट करता है कि 16.09.2020 दिनांकित एक अंतरिम आदेश के अनुसार, जिस पद पर याचिकाकर्ता का चयन किया गया था, उसे कार्यवाही विचाराधीन रहने के दौरान खाली रखने का निर्देश दिया गया था। तदनुसार, प्रतिवादी को याचिकाकर्ता को उक्त पद का लाभ देने का निर्देश दिया जाता है। जिस अवधि के लिए वह सेवा से बाहर रही है, उसे हालांकि उसकी योग्यता के अनुसार वरिष्ठता आदि सहित उसके काउंटर भागों के साथ समानता पर सभी काल्पनिक लाभ दिए जाएंगे, लेकिन 'कोई काम नहीं, कोई वेतन नहीं' के सिद्धांत पर किसी भी मौद्रिक लाभ का हकदार नहीं होगा।

(अरुण मोंगा), जे.

यह अनुवाद आर्टिफ़िश्यल इंटेलिजेंस टूल "सुवास" के जरिये अनुवादक की सहायता से किया गया है ।

अस्वीकरण - यह निर्णय पक्षकार को उसकी भाषा में समझाने के सीमित उपयोग के लिए स्थानीय भाषा मे अनुवादित किया गया है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है। सभी आधिकारिक एवं व्यवहारिक उद्देश्यों के लिए उक्त निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही प्रामाणिक होगा एवं निष्पादन और क्रियान्वयन के उद्देश्य से भी अंग्रेजी संस्करण ही मान्य होगा।